

सम्पादकीय

किसी सैन्य घटक के बिना
क्वाड न तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र
में शांति कायम करने में
समर्थ हो सकेगा और न ही
चीन की काट कर पाएगा

काठकोय में आयोजित क्वाड देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन विश्व व्यवस्था के निर्धारण में हिंदू-प्रशांत की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि का प्रतीक है। इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पर्वतीय यूरोप पर ठिका हुआ है। ऐसी स्थिति में क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और एस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों का जापान में बैठक करना और एशिया के भविष्य की रूपरेखा पर रणनीति बनाना यही संकेत करता है कि एशिया में शक्ति संतुलन ही अंततः वैशिक भू-राजनीति एवं भू-अर्थनीति में निर्णायक सिद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यही रही कि दूनिया के तीन प्रमुख क्षेत्रों में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हानी नहीं होने देना है। ये प्रमुख क्षेत्र रहे यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया। इसके पीछे अमेरिका का यह सोच रहा कि इनमें से कहीं भी अगर शक्ति संतुलन अमेरिका के विपरीत गया तो उसके लिए वैशिक महाशक्ति बने रह पाना संभव नहीं होगा। बाइडन प्रशासन द्वारा 2021 में जारी 'राष्ट्रीय सुरक्षा सामरिक मार्गदर्शन' में यही दोहराया गया है। उससे यही स्पष्ट होता है कि ही अमेरिका एक और महत्वाकांक्षी पहल कर रहा है। इसे 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा' नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और विद्यतनाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फ्रेमवर्क के उद्घाटन पर उपस्थित होना दर्शाता है कि भारत इसके सामरिक लाभ को समझता है। आपूर्ति शृंखला को लीचीला बनाना, 5जी तकनीक का सुरक्षित एवं भरोसेमंद विकास, उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन आदि इस गठजोड़ के प्रमुख उद्देश्य बताए जा रहे हैं। सूलिन ने डंके की चोट पर कहा कि इसकी धमक बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी। इसमें चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को टक्कर देने की पूरी संभावना है। यह क्वाड पुस के रूप में उसका औपचारिक विस्तार तो नहीं, किंतु अनौपचारिक तरीके से आकार लेने वाले इस ढांचे में चीन की काट करने की क्षमता जरूर है। क्वाड के चार मूल सदस्य ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुआयामी क्षमता रखते हैं। ऐसे में उन्हें स्वाभाविक रूप से इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का साझा नेतृत्व करना होगा। ये

अमेरिकी सुरक्षा के लिए दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों पर विराधियों का आधिपत्य होने से रोकना अनिवार्य है। पश्चिम एशिया और यूरोप में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। ईरान और रूस जैसे देश अमेरिका को परेशान करते आए हैं, लेकिन उनमें उतना आर्थिक एवं सैन्य बल नहीं, जिससे वे अमेरिका को मात दे सकें। केवल पूर्वी एशिया में स्थित वीन ही अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम दिखाई पड़ता है और वह इसके बराबर भी कस रहा है। अमेरिका भी इससे भलीभांति अवगत है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र ही इक्कीसवीं सदी के भविष्य को परिभाषित करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इस मामले में अमेरिकी नेतृत्व एवं भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि व्हाड के साथ चारों देश पहले ही इन्फास्ट्रक्चर, वैक्सीन, आपूर्ति शृंखला, सामरिक साझेदारी और सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में समझौते कर चुके हैं और उनमें से कुछ पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में साझेदारी के इस दायरे को बढ़ाना और नए सहयोगियों को उसमें जोड़ो? ही बुद्धिमत्ता होगी। अमूमन यही माना जाता है कि जिन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढाँचों में अधिक हितधारक होते हैं, वहां समन्वय, सहमति बनाकर अपेक्षित कार्य को शीघ्रता से संपादित करना संभव नहीं होता। इसलिए इस फ्रेमवर्क में विभिन्न पक्षों को देखते हुए उसकी कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाने के उपाय करने होंगे। बाइडन प्रशासन कहता आ रहा है कि उसका लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि 'लोकतांत्रिक देश वादों' और अपेक्षाओं पर खरे उत्तर सकते हैं और तानाशाही वाले देशों से बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं।'

कल्याणकारी योजनाओं से
दिव्यांगजनों को सशक्ति
बना रही है प्रदेश सरकार

प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर उन्हें सशक्त बना रही है। ये सभी योजनाएं दिव्यांगजनों को पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के अपने वृहतर उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं दिव्यांगजनों के आर्थिक, शैक्षणिक पुनर्वासन के साथ आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वासन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पैशन) योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं उनके भरण-पोषण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अंतर्गत पूर्व में ₹ 500 प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता था, उसको प्रदेश शेरड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर ₹ 1,000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से देने का आदेश जारी किया है। अद्यतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजन पैशन योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 89402.00 लाख के सापेक्ष ₹ 89401.98 लाख का व्यय करते हुए चर्तुर्थ किश्त में अद्यतन कुल 11,17,314 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। कुछावस्था पैशन योजना के अंतर्गत कुछ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को पूर्व में ₹ 2500 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर ₹ 3,000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से कर दिया है। उसी दर से लाभान्वित किया जा रहा है। अद्यतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुछावस्था पैशन योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 3900.00 लाख के सापेक्ष कुल 11,430 कुछ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना संचालित करते हुए प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा के अन्दर हो, को अधिकतम ₹ 10,000 के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि ₹ 3740.00 लाख के सापेक्ष कुल 19,964 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए संचालित शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा नियमावली के अन्तर्गत विभाग द्वारा 21 प्रकार की शल्य क्रियाओं के लिए प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष रुपये 8000 की दर से अनुदान देय था।

योगी सरकार का 6वां बजट सदन में पेश

बुंदेलखंड की विशेष योजना लिए 500 करोड़। बनारस में 5.1 प्रथमनंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़। मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़। की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट। काशी विश्वनाथ राजधानी पुल के लिए 500 करोड़। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़। प्राइवेट ट्रॉफी बोर्ड के बिजली बिल में 50 जून की छूट मिलती रहेगी। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उननित योजना लाई गई। योजना में गांव में सौलर लाइट लगाएगी सरकार। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़। सच्च भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट। कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विवर दर पाने का लक्ष्य। गंगा भुगतान के लिए 1 हजार का

के लिए 7373 करोड़ का बजट।
कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास
दर पाने का लक्ष्य। गनन
भुगतान के लिए 1 हजार करोड़

का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़। यीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट। बांदा कृषि विवि



देश में सिपेट केंद्र बनाने के लिए 35 प्रोजेक्ट करोड़। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य। समग्र शिक्षा अभियान

आत्मनिर्भरता का मंत्र और जनाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनी कल्याणकारी योजनाएं

अपने आदर्श और सही अर्थों में जनतंत्र जनता का शासन है। ऐसे में एक जनतांत्रिक राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता की आकांक्षाओं एवं जरूरतों को समझकर लोक कल्याणकारी नीतियां एवं योजनाएं बनाए। जब कोई भी जनतांत्रिक राज्य ऐसा करता है तो जनता जनतंत्र में एक प्रबल हिस्सेदार के रूप में उभरकर सामने आती है। इसीलिए मोदी सरकार लगातार जहां नई लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, वहीं पहले से चली आ रही योजनाओं का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही प्राप्त हो रहे अनुभवों एवं मिल रहे सुझावों के आधार पर पहले से चल रही योजनाओं में नए तत्व भी जोड़ रही हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की अनेक योजनाएं जैसे-पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत एवं उज्ज्वला जैसी लोकप्रिय योजनाएं समय के साथ और सबल ही हुई हैं। इसमें दो मत नहीं कि जनतांत्रिक राज्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभाधिक्यों का एक समूह विकसित करता है, जो उनका लाभ उठाते हुए सक्षम होकर समाज में आगे बढ़ता है। जो भी राजनीतिक दल शासन में रहकर इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करता है, उसके प्रति जनता की राजनीतिक ऊपर से ऐसूचिती भी देखी जाएगी।

प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद केंद्र एवं राज्य की दोनों सरकारों ने मुक्त राशन वितरण योजना की अवधि का विस्तार किया। इसके साथ ही

A photograph showing a close-up of a person's face and upper body. The person is wearing a bright red turban and a light-colored, vertically striped shirt. They appear to be looking down at their hands or a small object they are holding. In the background, there is a large, textured tree trunk and a blurred green landscape, possibly a field. The lighting suggests it might be late afternoon or early evening.

**सत्य को साक्षय की आवश्यकता नहीं होती
इसका साक्षात् प्रमाण है ज्ञानवापी परिसर**

पवित्र काशी के ज्ञानवापी परिसर का न्यायिक वीडियो सर्वेक्षण सार्वजनिक रिमर्श में है। 16 मई को इसके परिसर में अधिकता आयुक्त की कार्यगाही के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने के दावे के बाद संबंधित क्षेत्र पर अदालती प्रतिबंध है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जबसे इसे लेकर सुनवाई प्रारंभ हुई है, तबसे 1991 का पूजास्थल (विशेष प्रविधिन) अधिनियम भी चर्चा में है। इसे तत्कालीन नरसिंह राव सरकार द्वारा संसद से पारित कराया गया था। इसका उल्लेख वामपंथी-सेक्युलर वर्ग यह कहते हुए कर रहा है कि यह संसद से पारित कानून है। इसे चुनौती देना लोकतंत्र-संविधान का अपमान है। यदि ऐसा है तो फिर 2019 में संसद से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ इसी जमात ने देश के कई क्षेत्रों को हिंसा की आग में क्यों झोका? ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष पूजास्थल अधिनियम की वैधानिकता पर प्रश्न-उठा रहा और उसे निरस्त करने की मांग कर रहा है। इसे से क्युलर-लिंबरल वृन्दावा

की उक्ति का सबसे जीवंत उदाहरण है। मंदिर संरचना में नंदी का मुख बीते साढ़े तीन शताब्दियों से विपरीत दिशा की ओर होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि हिंदू मान्यता/आस्था के अनुसार किसी भी शिवलय में शिवलिंग/शिवमूर्ति की ओर देखते हुए ही नंदी की प्रतीतमा होती है। काशों का प्राचीन मंदिर 1194 से 1669 के बीच कई बार इस्मामी आक्रमण का शिकार हुआ, लोकन वह हर बार हिंदू प्रतिकार का साक्षी भी बना। औरंगजेब ने जिहादी फरमान जारी कर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों से मर्सिद बनाने का आदेश दिया। इसका मकसद केवल पराजितों को अपमानित करना था। इसी सोच के साथ औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा स्थित मंदिर को भी ध्वस्त किया। जब ज्ञानवापी परिसर में अदालत निर्देशित सर्वेक्षण पर कथित वजूखाने में प्राचीन शिवलिंग के प्रमाण मिले, तो एक वर्ग की ओर से हिंदू संस्कृति पर कृठाराघात करते हुए धृणित टिप्पणियां की गई। इनमें से कोई भी उस प्रकार की नृशंसता का शिकार नहीं हुआ, जैसे ईशनिदा के नाम पर फांसीसी शिक्षक सैमुअल पैटी और कमले श तिवारी हुए थे। इस्मामी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों/मूर्तियों को तोड़े? की मानसिकता का सटीक उल्लेख 'तारीख-ए-सुल्तान महमूद-ए-गजनवी' पुस्तक में मिलता है। इसके अनुसार जब गजनवी को एक पराजित हिंदू राजा ने मंदिर ध्वस्त न करने के बदले अकूत धन देने की पेशकश की, तब उसने कहा था, 'हमारे मजहब में जो कोई मूर्तिपूजकों के पूजास्थल को नष्ट करेगा, वह क्यामत के दिन बहुत बड़ा इनाम पाएगा और मेरा इरादा हिंदुस्तान के हर नगर से मूर्तियों का पूरी तरह से हटाना है।' इस तरह का उल्लेख इस्मामी आक्रान्तों के समकालीन इतिहासकारों या उनके दरबारियों द्वारा लिखे विवरण में सहज मिल जाता है। औरंगजेब के खूनी इतिहास पर लिखी गई 'मआसिर-ए-आलमगीरी' भी इसका एक प्रमाण है।

संक्षिप्त समाचार

मंडी हवाई अडे वें सामाजिक प्रभाव का होगा मूल्यांकन, प्रशासन ने सरकार को पत्र भेजकर जल्द मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने का किया आग्रह मंडी। मंडी जिले के बहु हल्के में प्रस्तावित ग्रीन फैल्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अडे को धारातल उतारने की हवाई अडे को धारातल घुट्ठा हो गई है। प्रशासन ने हवाई अडे सामाजिक प्रभाव यानी क्षेत्र के लोगों पर होने वाले असर का मूल्यांकन करवाने का निर्णय लिया है। सरकार को पत्र लिखकर जल्द मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की गई है। पर्यटन विभाग सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करवाएगा। कोविड की वजह से दो साल से मूल्यांकन का काम अटका था। हवाई अडे के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग ने गत सप्ताह निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के साथ इसकी विभाग की अपेक्षा थी। हवाई अडे के निर्माण के लिए उपलब्ध प्रशासन ने सरकार के निर्देश परिवर्ति के अंदर देने के निर्देश दिया है। सामाजिक प्रभाव की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कृषि संस्थानों के विरोध के लिए लोटे हुए बहुत अधिग्रहण से संबंधित जननिवाई होने की संभाजना न के बराबर लग रही है। सरकार ने अनिवार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत नियम भूमि अधिग्रहण करने का मन बनाया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

नोएडा प्राधिकरण की खुली पोल, श्रमिक कुन्ज के मकानों की स्थिति दर्यनीय

(आधुनिक समाचार सेवा)

देव मणि शुक्र

नोएडा। सेक्टर 93 के श्रमिक कुन्ज

गयी है। जबकि 99 बर्ष का नोएडा प्राधिकरण ने जिम्बदरी ली हुयी थी। अध्यक्ष ने आगे बताया कि द्वितीय में आज सुबह छज्जा गिरने से लोगों के हड्डकम्प मच गया।

गयी है। जबकि 99 बर्ष का नोएडा प्राधिकरण ने जिम्बदरी ली हुयी थी। अध्यक्ष ने आगे बताया कि द्वितीय में आज सुबह छज्जा गिरने से लोगों के हड्डकम्प मच गया।

हमारे नोएडा व्यूरो प्रभारी देव मणि शुक्र

ने मौके पर पहंच कर

स्थिति को देखा और

लोगों से बातचीत भी किया। आर डब्ल्यू ए

अध्यक्ष राहुल दवे ने

हमारे व्यूरो प्रभारी देव

मणि शुक्र से बातचीत

करते हुए बताया कि

यह सोसायटी नोएडा

प्राधिकरण ने 2002 में

75000 रुपये में

आवंटित किया था। आज 20 बर्ष

हुए इसे अविटोन किए हुए लोकन

यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो

है। आप दिन कहीं न कही मकानों

में नुकसान होता रहता है। इसी

कड़ी में आज यहाँ के अजय कुमार

अवलंब करने की कृपा करें।

तौरसिया 274 सी एवं मनीष 273

सी के गेट पर बना 3 फिट का

छज्जा पूरी तरह से ढे गया।

लेकिन भगवान की कृपा से कोई

अनहोनी घना नहीं हुआ।

इसके

अलागा भूमि बहुत

सारे मकानों की

स्थिति ऐसी ही बनी

हुई है। जिसकी

तारफ नोएडा

प्राधिकरण के कान

में जू नहीं रेग रही

है। अध्यक्ष ने नोएडा

एग्जामिनेशन

सोसायटी

में जर्जर मकानों का

अवलंब करे एवं उसकी मस्तम

नीलिंग राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं

प्राधिकरण कर दी गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) से

मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अन्य

प्रियों के लिए लोटे हुए

प्राधिकरण के लिए लोटे हुए

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य



एसके गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई नैनी, नैनी आईटीसी के अनुदेशकों से बात करते हुए।



आरके दुबे प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई भद्रोही नैनी आईटीसी की वेबसाइट का विमोचन करते हुए।

कार्यालय प्रधानाचार्य नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सीधे प्रवेश सुचना

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तावित व्यक्तियोगी में अगस्त 2021 में प्रारम्भ होने वाले शास्त्र में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग एवं नैनी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स क्लास, फिटर, ऐसिक कल्याणिंग, आटा एन्टी ऑफेलोल, कायर फ्रीमेनाल एवं इण्डस्ट्रीयल सोफ्टवर, नियोरिटी सार्किल, कल्पनाल हाईवेयर असेंबली एवं मेनेटेनेंस, सार्टिफिकेट हृनक न्यूट्रिट एप्लीकेशन (सीएनीएल), इलेक्ट्रिकल टेक्निकलिंग, रेफिनरीशन एन्ड प्रायर कम्प्रेसन, योगा अशिस्टेंट, लेलिंग टेक्नोलॉजी, सीटिंगनल्हॉम प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्पनाल टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए न्युनल सीधेक योग्यता हाईस्कूल उल्लिखित हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट www.nainiiti.com पर जाएँ Student's Zone → Online Form → Choose Course → Apply Now

यह आपने व्यवसाय कोर्स का चयन कर आपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवार कार्ड एवं 4 पासपोर्ट चाहज कोटीयाक के साथ प्रवेश कार्यालय में आपको करें।

नोट-: प्रवेश प्राप्त करने की अनितम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए

visit us at : www.nainiiti.com

प्रवेश कार्यालय :- त्रिलोकपुरी प्लाजा टीसरी मॉडिल,
एम.जी. मार्ग, चिकिता लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

फोन करें :- 0532-2695850, 9415608710, 6394370734,
7355448437, 6386474074, 6306080178, 9026359274

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य...

नैनी/इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं के पास अपना भविष्य बनाने का सुनहरा मोका है। ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य बनाने का मोका नैनी इंडिस्ट्रियल इंस्टीट्यूट दे रहा है। यह जापि बिना अतिरिक्त समय गणना से तीनों बोर्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर्ण प्रदेश के तकरीबन छोटीसाल लाख विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के साथ अच्छे करियर की भी चिंता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में चलने वाले कोर्सेज फॉर्म स्टडी के रूप में सामने आए हैं। थीरे-थीरे यह रोजगार की गारंटी बनते हैं। इसके अलावा आईटीआई में एक लाख से अधिक विद्यार्थी की मांग है। इसके विपरीत हर साल मात्र तीस हजार प्रशिक्षित युवा मिल रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों में सैकड़ों पदों के लिए आईटीआई पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में डेरों संभाननाएं हैं ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि पंखरागत कोर्स के साथ युवा आईटीआई की ओर ध्यान देकर बेहतर कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा

पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवत्तन दरूण स्वरजा से हुई खास बातचीत में उहने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पृष्ठ- गण सवाल

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्या है? इसके बारे में बताएं।

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो नैनी परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।



द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनसीबीटी-डीजीटी-नई दिल्ली, एनआईओएस - नई दिल्ली।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन से क्या लाभ है?

उत्तर- गर्तमान परिवृद्धि में पाठ्यक्रम आईटीआई द्वारा समय पर परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं?

उत्तर- कोण (कम्प्यूटर अपरेटर एण्ड प्रोग्रेमिंग आसिस्टेंट), फैटर, बेसिक कम्प्यूटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फायर प्रीवेशन एंड इंडिस्ट्रियल सेफ्टी, सिक्युरिटी सर्विस, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड मैटेनेंस इन कंप्यूटर एंड ऑफीसेन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग इन एयर कंट्रोल्यार्म, योग असिस्टेंट, वैल्डग ट्रैकोलॉजी, सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक्सियन, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, इत्यादि।

प्रश्न- आपके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्या अंतर है?

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ प्रमाणित है एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्टार (सिस्टर) प्रैंडिंग की गई है एवं एम.आई.एस.डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र भी नियुक्त किया गया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर इस प्रकार है- 0532-26958959, 9415608710, 9415608783, 9415608790, 7380468640, 6394370734।



आरके अग्रहरि अनुदेशक राजकीय आईटीआई नैनी, नैनी आईटीसी की प्रवेश विवरिका का विमोचन करते हुए।



आकांक्षा वर्मा टीवी एक्ट्रेस नैनी आईटीसी का भ्रमण करते हुए।



सृष्टि सिंह मिसेज एशिया पेसिफिक नैनी आईटीसी के छात्रों को साथ।